AMAR UJALA MY CITY Page 5

शिक्षकों का ब्यौरा 15 तक अपलोड नहीं किया तो दाखिलों पर लगेगी रोक

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सभी सहयुक्त कॉलेजों को कोर्सवार शिक्षकों का ब्यौरा यूनिवर्सिटी डाटा रिसोर्स सेल के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए एक बार फिर से निर्देश दिए हैं। 15 जून तक ब्यौरा अपलोड न होने पर नए सत्र से दाखिले प्रतिबंधित करने तथा मान्यता वापस लेने की चेतावनी दी गई है। लविवि कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने पत्र जारी कर कई महाविद्यालयों द्वारा अभी तक शिक्षकों का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप में अपलोड न होने कड़ी नाराजगी जताई है। कई कॉलेजों के बारे में शिकायत दर्ज कराई गई है कि वे निर्धारित संख्या में शिक्षक नहीं रखते हैं। अनुमोदन कराने के बाद वे बेहद कम वेतन वाले बिना अनुमोदित शिक्षकों से पढ़ाई कराते हैं। इसको देखते हुए विवि ने यूडीआरसी पोर्टल पर पूरा ब्यौरा अपलोड करने का निर्देश दे रखा है। इसमें कॉलेजों को उनके यहां पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम में पढ़ाने वाले शिक्षक, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, वेतन बैंक खाता नंबर आदि का पूरा ब्यौरा देना है। इसके साथ ही शिक्षक का फोटो भी पोर्टल पर अपलोड करना है। ऐसा न करने पर उनके दाखिले रोक दिए जाएंगे। विवि प्रशासन पहले भी यह निर्देश जारी कर चुका है पर महाविद्यालय इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको देखते हुए विवि प्रशासन ने इस बार सख्ती करते हुए प्रवेश रोकने के साथ ही मान्यता वापस लेने की चेतावनी दी है।

RASHTRIYA SAHARA Page 5

लविवि से संबद्ध डिग्री कालेजों को रजिस्ट्रार ने भेजा प्रोफार्मा

लखनऊ (एसएनबी)। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध सेल्फ फाइनेंस व एडेड कॉलेजों में चल रहे सेल्फ फाइनेंस कोर्सों में पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसरों के साथ हो रहे फर्जीवाड़े पर लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार विनोद कुमार सिंह ने सभी 170 डिग्री कॉलेजों को प्रोफार्मा भेजा है। 'राष्ट्रीय सहारा' में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए डॉ सिंह ने 150 के करीब सेल्फ फाइनेंस कॉलेज और 20 एडेड कॉलेजों में चल रहे सेल्फ फाइनेंस कोर्सों में पढ़ा रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों के बाबत पूरी जानकारी मांगी है।

प्रोफार्मा में सेल्फ फाइनेंस कोर्स का नाम, उसमें पढ़ा रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों के नाम, नियुक्ति की तिथि, किए जा रहे भुगतान, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अनुमोदित पत्र संख्या, वेतन भुगतान के बारे में अन्य जानकारियां हर हाल में लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजने को कहा गया है। यही नहीं अनुमोदित

डिग्री कॉलेजों को भर कर भेजना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम और वेतन भुगतान के सारे ब्यौरे

असिस्टेंट प्रोफेसरों की पूरी सूची यूडीआरसी पोर्टल और संबंधित डिग्री कॉलेज के वेबसाइट इत्यादि पर भी स्पष्ट रूप से दिखने के लिए भी ताकीद किया गया है।

इस बाबत लविवि के रजिस्ट्रार विनोद कुमार सिंह का कहना है कि जुलाई 2020 से एक अभियान चलाया जाएगा और जिस भी कॉलेज के सेल्फ फाइनेंस कोर्सों के अनुमोदित असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में सूचनाएं भ्रामक और गड़बड़ी पाई जाएगी, उस डिग्री कॉलेज की संबद्धता खत्म करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

NBT Page 4

सेल्फ फाइनैंस कोर्स में पढ़ाएंगे युवा शिक्षक!

पासआउट स्कॉलर्स को मिलेगा मौका, जल्द शुरू होगी 100 से ज्यादा संविदा पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया

■ शिवम अग्निहोत्री, लखनऊः लखनऊ विश्वविद्यालय (एलयू) अब सेल्फ फाइनैंस कोर्स पढ़ाने के लिए युवा शिक्षकों को ज्यादा प्राथमिकता देगा। इसके अलावा एलयू से पासआउट स्कॉलर्स को भी पढ़ाने का मौका देगा। एलयू प्रशासन के मुताबिक, जल्द ही 100 से ज्यादा नए संविदा शिक्षकों के पदों का सृजन करने जा रहा है। शासन की फाइनेंस कमिटी जल्द ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी।

एलयू में लगभग 30 से ज्यादा सेल्फ फाइनैंस कोर्स चलाए जा रहे हैं। इनमें 72 संविदा के टीचर और कुछ रेगुलर शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन कम शिक्षक होने की वजह से ज्यादा लोड पड़ रहा है। इसे देखते हुए एलयू संविदा शिक्षकों के पद निकालने जा रहा है। डीन रिक्रूटमेंट असेसमेंट प्रो. मुनका खन्ना के मुताबिक, लगभग 100 से ज्यादा संविदा शिक्षकों के पद निकाले जाएंगे। खास बात यह है कि इन पदों पर एलयू से हाल ही में पासआउट स्कॉलर्स भी आवेदन कर सकते हैं।

फीस का 75% पैसा वेतन पर खर्च होगा

प्रो. मुनका खन्ना ने बताया कि सेल्फ फाइनेंस की फीस का 75 प्रतिशत हिस्सा एलयू शिक्षकों के वेतन पर खर्च कर सकता है। हालांकि, शासन की फाइनैंस कमिटी जल्द रिक्रूटमेंट को लेकर बैठक कर यह तय करेगी। वहीं, अगर हालात ठीक रहे तो ओपन इंटरव्यू होंगे।

हर साल होगा रिव्यू

संविदा पर रखे गए इन शिक्षकों का हर साल रिव्यू किया जाएगा। इसी आधार पर उनका कॉन्ट्रेक्ट आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षक तीन से लेकर पांच साल के लिए कॉन्ट्रेक्ट पर रखे जाएंगे।

शिक्षकों का ब्योरा अपलोड नहीं मान्यता रद

■ **एनबीटी, लखनऊः** लखनऊ विश्वविद्यालय (एलयू) से सम्बद्ध ज्यादातर कॉलेज ने शिक्षकों का ब्योरा अपलोड नहीं किया है। इसे लेकर एलयू प्रशासन ने कॉलेजों को 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी डेटा रिसोर्स सेंटर (यूडीआरसी) के पोर्टल पर ब्योरा अपलोड करने के लिए कहा है। ऐसा न करने वाले कॉलेजों को मान्यता रद करने की चेतावनी दी है। एलयू कुलसचिव विनोद कुमार सिंह ने बताया कि सम्बद्ध कॉलेजों को शिक्षकों का ब्योरा यूडीआरसी पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कॉलेजों का ये भी बताना होगा कि उनके यहां कितने अप्रूव्ड और नॉन अप्रूव्ड शिक्षक हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार कॉलेजों को निर्देश दिए जाते रहे हैं, लेकिन शिक्षकों का ब्योरा अपलोड नहीं किया।

HINDUSTAN Page 7

एलयू ने कॉलेजों से शिक्षकों का ब्योरा मांगा

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सभी सहयुक्त महाविद्यालयों से सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले शिक्षकों का ब्योरा मांगा है। महाविद्यालय प्रबंधनों को 15 दिन का समय दिया है। इस दौरान शिक्षकों के आधार और पैन कार्ड तक की जानकारियां मांगी गई हैं।

एक ही शिक्षकों के कई महाविद्यालयों में पढ़ाने की शिकायतें के चलते यह कार्रवाई की गई है। कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किए हैं। कुलसचिव ने बताया कि इससे पहले भी जानकारी मांगी गई थी।

PIONEER Page 3

एलयू ने तलब की निजी कालेजों से 15 दिन में रिपोर्ट

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

निजी महाविद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की कमी के साथ हो रहे आर्थिक शोषण की शिकायत पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने निजी कालेज प्रबंधन से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की है। विवि के कुलसचिव ने निजी कॉलेजों को निर्देश जारी कर शिक्षकों के बारे में पूरी रिपोर्ट तलब करते हुए पूरा ब्यौरा यूआरडीसी वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। उत्तर प्रदेश के वित्त पोषित महाविद्यालय शिक्षक महासंघ ने निजी महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को लेकर पिछले दिनों लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश से शिकायत की थी। शिकायत में महासंघ की तरफ से निजी कालेज प्रबंधन द्वारा शिक्षकों के शोषण की बात कही गई थी। जिसको संज्ञान में लेते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुल सचिव विनोद कुमार सिंह ने निजी प्रबंधन कॉलेजों को नोटिस जारी कर कॉलेज में कार्यरत शिक्षकों के बारे में रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट में शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता से लेकर उनको दिए जाने वाले वेतन पदों की संख्या वेतनमान के बैंक की स्टेटमेंट की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही उन्होंने कालेजों से यूआरडीसी के पोर्टल पर पूरी जानकारी अपलोड करने को कहा है विश्वविद्यालय के कुलसचिव के मुताबिक यूजीसी के नियमानुसार कॉलेजों को पोर्टल पर जानकारी देना अनिवार्य है। जिसके साथ कालेजों को अपलोड करने को कहा गया है।